

बैंकों का नजीकरण

प्रलम्बिस् के लयिः

भारत में बैंकगि और संबधति कानून, RBI के कार्य, परसिंपत्तपुनरनरिमाण कंपनी (बैड बैंक) ।

मेंन्स के लयिः

बैंकों का नजीकरण, इसके महत्त्व और संबधति मुद्दे, उदारीकरण से पहल के वर्षो में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नजीकरण के लयि 'अग्रमि कार्रवाई (Advanced Action)' करने की प्रक्रयि में है ।

- सरकार [मुद्रासफीत](#) पर लगाम लगाने के साथ-साथ आर्थिक स्थरिता और वकिस को बनाए रखने के लयि नरितर प्रयससत है ।

नजीकरणः

- सरकार से नजी क्षेत्र में स्वामतिव, संपत्तयिा व्यवसाय के हसत्तांतरण को नजीकरण कहा जाता है । इसमें सरकार इकाई या व्यवसाय की स्वामी नहीं रह जाती है ।
- नजीकरण कंपनी में अधिक दक्षता और नषिपक्षता लाने के लयि कयिा जाता है, ऐसा सुधार जसिके बारे में एक सरकारी कंपनी चतिति नहीं होती है ।
- भारत 1991 के ऐतहिसिक सुधार बजट में नजीकरण को बढ़ावा दयिा गया जसि '[नई आर्थिक नीतयिा LPG नीतयि](#)' के रूप में भी जाना जाता है ।

पृष्ठभूमिः

- सरकार ने 1969 में [14 सबसे बड़े नजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण](#) करने का नरिणय लयिा । इसका उद्देश्य बैंकगि क्षेत्र को तत्कालीन सरकार के समाजवादी दृष्टिकोण के साथ समायोजति करना था ।
 - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 1955 में ही राष्ट्रीयकरण कर दयिा गया था और 1956 में बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कयिा गया था ।
- पछिले 20 वर्षों में वभिनिन सरकारें [सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरमों \(PSU\)](#) बैंकों के नजीकरण के पक्ष में और वरिोध में रही हैं । 2015 में सरकार ने नजीकरण का सुझाव दयिा था लेकिन तत्कालीन [भारतीय रजिस्व बैंक \(RBI\)](#) के गवरनर ने इस वचिार का समर्थन नहीं कयिा ।
- नजीकरण के मौजूदा कदम पूरी तरह से बैंकों के स्वामतिव वाली [परसिंपत्तपुनरनरिमाण कंपनी \(बैड बैंक\)](#) की स्थापना के साथ वत्तीय क्षेत्र की चुनौतयिों के लयि बाज़ार के नेतृत्व वाले समाधान खोजने के दृष्टिकोण को रेखांकति करते हैं ।
- केंद्र ने 2021-22 के [बजट](#) में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नजीकरण की घोषणा की, लेकिन अभी तक संबधति बैंकगि कानूनों में संशोधन नहीं कयिा है ताकतिउनमें अपनी बहुमत हसिसेदारी की बकिरी की अनुमतयि मिल सके ।

नजीकरण का कारणः

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वत्तीय स्थतिति में गरिावटः**
 - वर्षों से पूंजीगत नविश और शासन सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वत्तीय स्थतिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं कर पाए हैं ।
 - उनमें से कई के पास नजी बैंकों की तुलना में तनावग्रस्त परसिंपत्तयिों का उच्च स्तर है और लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण तथा लाभांश भुगतान रकिर्ड के मामले में भी पीछे है ।
- एक दीर्घकालिक परयिोजना का हसिसाः**
 - दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नजीकरण से एक दीर्घकालिक परयिोजना की शुरुआत होगी, जसिके तहत भारतीय बैंकगि क्षेत्र में कुछ चुनदिा सार्वजनिक बैंकों की परकिल्पना की गई है । यह कार्य या तो मज़बूत बैंकों को समेकति करके या फरि बैंकों का नजीकरण कर कयिा

जाएगा।

- सरकार की प्रारंभिक योजना चार बैंकों के नजीकरण की थी। पहले दो बैंकों के सफल नजीकरण के बाद सरकार आने वाले वित्तीय वर्षों में अन्य दो या तीन बैंकों के वनिविश पर ज़ोर दे सकती है।
 - यह नरिणय सरकार, जो कबैंकों में सबसे बड़ी हसिसेदार है, को बैंकों को वर्ष-प्रतवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायतव से मुक्त करेगा।
 - बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परणामस्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी।
- **बैंकों को मज़बूती प्रदान करना:**
 - सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा साथ ही नजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।
 - **अलग-अलग समतियों की सफ़ारशें:**
 - कई समतियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हसिसेदारी को 51 प्रतशित तक सीमति करने का प्रस्ताव रखा है:
 - नरसमिहन समति ने हसिसेदारी को 33 प्रतशित तक सीमति करने की बात की थी।
 - पी.जे. नायक समति ने हसिसेदारी को 50 प्रतशित से कम करने का सुझाव दिया था।
 - RBI के एक कार्यकारी समूह ने हाल ही में बैंकगि क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है।
 - **बड़े बैंकों का नरिमाण:**
 - नजीकरण का एक उद्देश्य बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक नजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े नजी बैंकों में वलिय नहीं कया जाता है, तब तक वे उच्च जोखमि लेने की क्षमता और उधार देने की क्षमता वकिसति नहीं कर सकते हैं।
 - ऐसे में नजीकरण एक बहुआयामी कार्य है, जसिमें कई चुनौतियों से नपिटने और नए वचिारों की खोज करने के लयि सभी दृष्टकिण पर वचिार कया जाता है, लेकनि यह सभी हतिधारकों को लाभान्वति करने के लयि एक अधिक सतत् और मज़बूत बैंकगि प्रणाली वकिसति करने का मारग प्रशस्त कर सकता है।

संबंधति मुद्दे:

- **क्रोनी कैपटिलज़िम को बढ़ावा:**
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नजीकरण बैंकों को नजी कंपनयिों को बेचने के समान है, जनिमें से कई ने PSBs के ऋण को वापस नहीं कया है जसिसे क्रोनी पूँजीवाद को बढ़ावा मला है।
- **नौकरी के नुकसान:**
 - नजीकरण से बेरोज़गारी, शाखा बंद होना और वित्तीय बहषिकरण जैसी गतविधियिों उत्पन्न होंगी।
 - नजीकरण से **अनुसूचति जातयिों, अनुसूचति जनजातयिों और अन्य पछिड़ा वर्ग (ओबीसी)** के लयि रोजगार के अवसर कम होंगे क्योकि नजी क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लयि आरक्षण नीतयिों का पालन नहीं करता है।
- **कमज़ोर वर्गों का वित्तीय बहषिकरण:**
 - नजी क्षेत्र के बैंक अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों की आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रति करते हैं, जसिसे समाज के कमज़ोर वर्गों, वशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय बहषिकार होता है।
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकगि की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को सुनश्चिति करते हैं।
- **बेलआउट ऑपरेशन:**
 - बैंक यूनयिनों ने नजीकरण प्रक्रया को कॉरपोरेट डफिल्टरों के लयि "बेलआउट ऑपरेशन" का नाम दिया है।
 - बड़े पैमाने पर फँसे ऋण के लयि नजी क्षेत्र ज़मिमेदार हैं और उन्हें इस अपराध की सज़ा मलिनी चाहयि लेकनि सरकार बैंकों को नजी क्षेत्र के हवाले कर उन्हें पुरस्कृत कर रही है।

आगे की राह

- PSBs के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा। ऐसा करने का एक उपाय पी.जे. नायक समति द्वारा सुझाया गया था, जहाँ सरकार और शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र नयिकृतयिों (जसिके संबंध में सारे कार्य बैंक बोर्ड ब्यूरो को करने थे लेकनि वह अक्षम रहा) के बीच दूरी रखने की अनुशंसा की गई थी।
- अंधाधुंध नजीकरण के बजाय PSBs को **जीवन बीमा नगिम (LIC)** जैसे नगिम में रूपांतरति कया जा सकता है। सरकारी स्वामतिव बनाए रखते हुए इनका नगिमीकरण PSBs को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. शासन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

1. प्रत्यक्ष वदिशी नविश अंतर्वाह को प्रोत्साहति करना
2. उच्च शकिषण संस्थानों का नजीकरण
3. नौकरशाही का आकार कम करना
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरो की बकिरी/ऑफलोडगि

भारत में राजकोषीय घाटे को नयितरति करने के उपायों के रूप में उपरोक्त में से कसिका उपयोग कया जा सकता है?

- (A) केवल 1, 2 और 3
(B) केवल 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 4
(D) केवल 3 और 4

उत्तर: (D)

- सामान्य तौर पर राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये कई उपाय करती है जैसे कर-आधारित राजस्व बढ़ाना, सब्सिडी कम करना, वनिविश आदि।
- नौकरशाही का आकार घटाने के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेरों को बेचने/ऑफलोड करने से राजकोषीय घाटे में कमी आती है।
- गंतव्य और एफडीआई प्रवाह के प्रभाव को जाने बिना राजकोषीय घाटे पर इसके वास्तविक प्रभाव को निर्धारित करना मुश्किल है। उच्च शक्ति संस्थानों के नजीकरण से स्थिति में सुधार हो सकता है लेकिन इसका प्रभाव राजकोषीय घाटे को कम करने में कारगर नहीं हो सकता है।
- अतः कथन 3, 4 सही हैं और कथन 1, 2 सही नहीं हैं। अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।

स्रोत : द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/privatisation-of-banks-2>

